

संक्षिप्त समाचार

मजदूरों का सांकेतिक धरना जारी

रुद्रपुर, एजेंसी। सिड्कुल की कंपनी में श्रम कानून का पालन करने की मांग को लेकर तुकास टीवीएस मजदूर संघ का सांकेतिक धरना मंगलवार को भी जारी रहा। गांधी पार्क स्थित धरना स्थल पर संघन के महामंत्री बसंत गोव्यामी, दीवान सिंह, हरीश राणा, मानवर सिंह, रवींद्र सिंह, धन सिंह, सुंदेंद्र सिंह आदि ने धरना दिया।

एसएसपी के दरबार में 14 शिकायतें आईं

काशीपुर, एजेंसी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने मुरादाबाद रोड डिजाइन सेटर विश्व अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 14 फाइलिंगों की शिकायतें सुनीं। एसएसपी ने कुछ फरियादियों की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। अन्त समयोंके विषय में अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करते हुए प्रकरण को एक साथ के भीतर निस्तारण करने के लिए कहा। बता दें कि चुनावी माहौल के कारण एसएसपी के जनता दरबार में इस बार कम शिकायतें आई हैं।

मेलाघाट में संदिग्ध हालात में मृतमिले छह बदंदर

खटीमा, एजेंसी। मेलाघाट गांव स्थित एक खेत में मंगलवार को संदिग्ध हालात में छह बदंदर मृत मिले। बान विभाग की टीम ने मौके पर हुंचाक बदंदर के शवों को कब्जे में लिया। बुधवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा।

बन विभाग की एसडीओ सचिवता वर्षा ने बताया कि मुबह के समय मेलाघाट गांव में खेत किनारे बदंदरों के शव पड़े हैं जो कोई मूर्छा नहीं थी। बदंदरों की नाक से खून बह रहा था। जिसे देखकर बदंदरों के आपाती संघर्ष में मौत होने की आशंका है। हालांकि ये असली वर्षा के चलते क्लाउंस्टोर्ट रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकती। टीम ने जांच के लिए गिर्ही और फसलों के सैंपल एकत्र किए हैं। फसलों में किए गए कीटोनाशक के उपयोग से भी बदंदर की मौत हो सकती है। बुधवार को बदंदरों का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

गन्ना मूल्य भुगतान की मांग

बाजपुर, एजेंसी। गन्ना मूल्य भुगतान सहित चार सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उहोंने चीनी मिल महाप्रबंधक द्वारा रियों को ज्ञान सौपकर जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

मंगलवार दोपहर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हारिंद्र सिंह लाडी की अमुवाल कांग्रेसी और किसान एकत्र होकर चीनी मिल प्रशासनिक कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मिल महाप्रबंधक हबीब सिंह को चार सूत्री मांगों का ज्ञान सौपा। लाडी ने कहा कि पेराई सत्र शुरू हुए एक माह बीत चुका है। इसके बावजूद मिल प्रशासन की तरफ से किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा। कहा कि किसानों को चीनी मिल से गन्ना बीज और खाद्य उत्पादकरण कराया जाए। गन्ना सोसायटी से पूर्व की भाँति किसानों को दो रुपय प्रति छिंटल बढ़ाती दी जाए। बहाने किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष नवदीप सूनू कंगा, परमजीत सिंह हांडा, कदरी अहमद, लीलाकर सैनी, गोडी, मनू सिंह, जगजीत सिंह संधु आदि थे।

202 नामांकन रद्द, अब मैदान में बचे 6238 प्रत्याशी, आज नामापसी का मौका

देहरादून, एजेंसी। नगर निकायों में 31 दिसंबर और एक जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच हुई। मेयर पद के लिए 103 नामांकन आए, जिनमें से दो रद्द हो गए। उत्तराखण्ड के 100 नगर निकायों में दो दिन की जांच के बाद 202 नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। आज बहस्तरित को प्रत्याशियों को नामापसी का मौका दिया जाएगा। इसके बाद अंतिम सूत्री जारी हो जाएगी। नगर निकायों में 31 दिसंबर और एक जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच हुई। मेयर पद के लिए 103 नामांकन आए, जिनमें से दो रद्द हो गए। 43 नगर पालिकाएँ में अध्यक्ष पद के लिए 285 नामांकन आए, जिनमें से 20 रद्द हुए। 46 नं पंथ अध्यक्ष पद के लिए 302 नामांकन आए, जिनमें से 12 रद्द हुए। मेयर-अध्यक्ष के कुल 690 में से 34 रद्द हो गए। अब 656 बचे हैं। इनमें मेयर के 101, नगर अध्यक्ष के 265 और नं पंथ अध्यक्ष पद के 290 नामांकन बचे हैं। तीन जनवरी को चुनाव चिह्न का आवेदन किया जाएगा। 100 निकायों में 5750 नामांकन पार्षद और वार्ड सरस्य के लिए आए, जिनमें से 168 रद्द होने के बाद अब 5582 नामांकन बचे हैं।

फिरोजपुर, अमृतसर, देहरादून, भटिंडा से प्रयागराज को चलेंगी सीधी ट्रेन, रेलवे ने जारी की समय सारिणी

देहरादून, एजेंसी। महाकुंभ मेला अधिक में अलग-अलग तिथियों में पंजाब के भटिंडा, अमृतसर, फिरोजपुर, हिमाचल देहरादून और देश की राजधानी दिल्ली से अमृकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले के लिए रेलवे ने पंजाब, हिमाचल, दिल्ली के लिए महाकुंभ ट्रेन की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है।

रेलवे ने जारी की राजधानी दिल्ली से अलग-अंदौरा, अमृतसर, पिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अंदौरा, उत्तराखण्ड के लिए महाकुंभ संशल ट

संक्षिप्त खबरें

गैंगस्टर के मामले में भाजपा

नेता गिरफतार

गजियाबाद। गैंगस्टर के मामले में

वाडिल चल रहे भाजपा नेता अनुज

कसाना को इंदिरापुरम थाना पुलिस

ने गिरफतार कर लिया। इस सूचना के

मिलते ही इंदिरापुरम पर दंडने

भाजपा को एक वार्कर्कट पांच बूचक गये।

आज सुबह भाजपाईयों ने न केवल

जमकर हंगामा किया बल्कि पुलिस

पर भाजपा नेता का उत्पादन करने

और उसपर जबरन गैंगस्टर लगाने के

अरोपण जबरन भाजपा के बाहर

धरने पर भी बैठ गये। इस संदर्भ में

जहां इंदिरापुरम पुलिस भाजपा नेता

की गिरफतारी को नियमसंगत बता रही

है वहीं पुलिस का वह भी कहना है कि

गिरफतार किये गये अनुज कसाना के

उत्पादन करने का अधिकारी

दर्ज है। वहीं दूसरी ओर भाजपाईयों व

अनुज कसाना के परिजनों का कहना

है कि पुलिस उत्पादन के राजनीतिक

विविध का तहस-नहस करने पर तुली

हुई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा

अनुज कसाना के परिजनों का कहना

है कि आज तक जहां

भाजपा नेता कार्यकर्ताओं के साथ

थाने के बाहर धरने पर भैंठे हुए थे

वहीं पुलिस अधिकारी भाजपा नेता औं

को इस मामले में किंवदन करने का

प्रयास कर रहे थे।

भाजपा युवा मोर्चा ने

किया थाने पर प्रदर्शन

गजियाबाद। भारतीय जनता पार्टी

के युवा मोर्चा के मॉडल अध्यक्ष पर

गैंगस्टर लाये जाने के बाद मोर्चा के

कार्यकर्ताओं ने इंदिरापुरम थाने पर

प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता

महानगर अध्यक्ष सचिन ढेढ़ा व परावर्थन

पूर्ण नाम के नेतृत्व में याचिनी

परावर्थन के गैंगस्टर की अपनी कार्यकर्ता

को उचित ठहराया है।

पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम का

लेकर हुई रिहाई

गजियाबाद। नम्न भारत रेस के अलाए

प्रोजेक्ट को हारी झड़ी दिखाने के लिए

पीएम नेतृत्व में वार्षिकी को

फिर से कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है।

हालांकि अभी तक इस तारीख को

गैंगस्टर को हारी झड़ी दिखायी दी

है। लेकिन पुलिस और प्रशासन के

अधिकारी सम्पादित कार्यक्रम को

लेकर फिर से तैयारियों में जुट गए हैं।

पीएम का साहित्याकाद और अरारटीएस

स्टेशन से नमो भारत देने में सावर्ण के

अनावश्यक घराने का अधिकारी

प्रस्तावित है। इसके बाद वह अग्रे के

प्रोजेक्ट को हरी झड़ी दिखायी दी। पहले

यह कार्यक्रम 29 दिसंबर को होना

था। लेकिन पूर्ण प्रधानमंत्री मनोहर

लोडी की गई है।

लेकिन पुलिस और प्रशासन के

अधिकारी सम्पादित कार्यक्रम को

लेकर फिर से तैयारियों में जुट गए हैं।

पीएम का साहित्याकाद और अरारटीएस

स्टेशन के बारे में याचिनी

को अनावश्यक घराने का अधिकारी

प्रस्तावित है। इसके बाद वह अग्रे के

प्रोजेक्ट को हरी झड़ी दिखायी दी। पहले

यह कार्यक्रम 29 दिसंबर को होना

था। लेकिन पूर्ण प्रधानमंत्री मनोहर

लोडी की गई है।

लेकिन पुलिस और प्रशासन के

अधिकारी सम्पादित कार्यक्रम को

लेकर फिर से तैयारियों में जुट गए हैं।

पीएम का साहित्याकाद और अरारटीएस

स्टेशन के बारे में याचिनी

को अनावश्यक घराने का अधिकारी

प्रस्तावित है। इसके बाद वह अग्रे के

प्रोजेक्ट को हरी झड़ी दिखायी दी।

लेकिन पुलिस और प्रशासन के

अधिकारी सम्पादित कार्यक्रम को

लेकर फिर से तैयारियों में जुट गए हैं।

पीएम का साहित्याकाद और अरारटीएस

स्टेशन के बारे में याचिनी

को अनावश्यक घराने का अधिकारी

प्रस्तावित है। इसके बाद वह अग्रे के

प्रोजेक्ट को हरी झड़ी दिखायी दी।

लेकिन पुलिस और प्रशासन के

अधिकारी सम्पादित कार्यक्रम को

लेकर फिर से तैयारियों में जुट गए हैं।

पीएम का साहित्याकाद और अरारटीएस

स्टेशन के बारे में याचिनी

को अनावश्यक घराने का अधिकारी

प्रस्तावित है। इसके बाद वह अग्रे के

प्रोजेक्ट को हरी झड़ी दिखायी दी।

लेकिन पुलिस और प्रशासन के

अधिकारी सम्पादित कार्यक्रम को

लेकर फिर से तैयारियों में जुट गए हैं।

पीएम का साहित्याकाद और अरारटीएस

स्टेशन के बारे में याचिनी

को अनावश्यक घराने का अधिकारी

प्रस्तावित है। इसके बाद वह अग्रे के

प्रोजेक्ट को हरी झड़ी दिखायी दी।

लेकिन पुलिस और प्रशासन के

अधिकारी सम्पादित कार्यक्रम को

लेकर फिर से तैयारियों में जुट गए हैं।

पीएम का साहित्याकाद और अरारटीएस

स्टेशन के बारे में याचिनी

को अनावश्यक घराने का अधिकारी

प्रस्तावित है। इसके बाद वह अग्रे के

प्रोजेक्ट को हरी झड़ी दिखायी दी।

लेकिन पुलिस और प्रशासन के

अधिकारी सम्पादित कार्यक्रम को

लेकर फिर से तैयारियों में जुट गए हैं।

पीएम का साहित्याकाद और अरारटीएस

स्टेशन के बारे में याचिनी

को अनावश्यक घराने का अधिकारी

प्रस्तावित है। इसके बाद वह अग्रे के

प्रोजेक्ट को हरी झड़ी दिखायी दी।

लेकिन पुलिस और प्रशासन के

अधिकारी सम्पादित कार्यक्रम को

लेकर फिर से तैयारियों में जुट गए हैं।

पीएम का साहित्याकाद और अरारटीएस

स्टेशन के बारे में याचिनी

को अनावश्यक घराने का अधिक

पास/फेल की बजाय समग्र विकास/जीवन कौशल की नीतियाँ बनाएं

नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत कक्षा 1 से 8 तक के किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता था। हालांकि अब इन छात्रों को फेल किया जा सकेगा। साथ ही फेल छात्रों को 2 महीने के भीतर फिर से परीक्षा का अवसर मिलेगा। अगर इसमें भी फेल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रोनॉट नहीं किया जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की नो-डिटेंशन पॉलिसी के अनुसार, किसी भी छात्र को तब तक फेल या स्कूल से निकाला नहीं जा सकता, जब तक वह कक्षा 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। लेवल 8 तक के सभी विद्यार्थियों को स्वचालित रूप से अगली कक्षा में पटोन्नत कर दिया जाएगा। नीति का मुख्य बिंदु यह है कि कक्षा 8 तक, पारंपरिक अर्थों में कोई ह्लपरीक्षाह नहीं होती है।



डा सत्यवान सौरभ (लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार)

नो डिंडेंशन पॉलिसी के तहत कक्षा 1 से 8 तक के किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता था। हालांकि अब इन छात्रों को फेल किया जा सकता है। साथ ही फेल छात्रों की 2 महीने के अवधि तरिके से प्रीक्षण का अवसर मिलेगा। अगर इसमें भी फेल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्ट नहीं किया जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की नो-डिंडेंशन पॉलिसी के अनुसार, किसी भी छात्र को तब तक फेल या स्कूल से निकाला नहीं किया जा सकता, जब तक वह कक्षा 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर सकता। कक्षा 5 और 8 में छात्रों के लिए नो-डिंडेंशन पॉलिसी को खत्म करना भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सुरक्षा की गई इस नीति का उद्देश्य छात्रों की असफलता को रोककर शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना था। हालांकि, सीखने के परिणामों में गिरावट की चिंताओं के साथ, संशोधन अकादमिक सुधार पर जोर

देकर पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। नॉ-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने से यह सुनिश्चित होता है कि छात्र शिक्षा प्राप्त करना जारी रखें, भले ही वे अकादमिक रूप से संघर्ष करते हों, जिससे सार्थभौमिक पहुँच के सिद्धांत को बल मिलता है। जिन छात्रों को असफलता के कारण निष्कासित कर दिया जाता था, उन्हें अब परीक्षा फिर से देने और सुधारात्मक सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

असफल छात्रों को रोकरक, नीति संक्रिय भागीदारी और जवाबदेही को प्रोत्साहित करती है, जबकि अपी भी शिक्षा तक सार्थभौमिक पहुँच को प्राथमिकता देती है। कक्षा 5 में असफल होने वाले छात्रों को अब अगली कक्षा में जाने से पहले सुधार करने का मौका मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे पीछे न छूट जाएँ। नीति में सुधारात्मक निर्देश के प्रावधान शामिल हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी छात्र शैक्षणिक संघर्ष के कारण शिक्षा से वंचित न रहे, न्यायसंगत पहुँच को

बढ़ावा दिया जाता है। उदाहरण के लिए: कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को विशेष सहायता और पुनः परीक्षा के अवसर मिलते हैं, जिससे उन्हें शिक्षा प्रणाली में बने रहने में मदद मिलती है। माता-पिता संघर्षरत छात्रों की पहचान करने और प्रगति की निगरानी करने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी बच्चों को, चाहे उनका प्रदर्शन कैसी भी हो, युणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। माता-पिता शिक्षकों के साथ नियमित संचार के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि शैक्षणिक विफलता के कारण कोई भी बच्चा अनदेखा न हो। नीति का उद्देश्य छात्रों को सफल होने के कई अवसर देकर उन्हें शिक्षा प्रणाली में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें स्कूल छोड़ने से रोकना है। नीति परिवर्तन के बाद, कक्षा 8 में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने का एक और मौका दिया जाता है, जिससे स्कूल छोड़ने की दर कम हो जाती है। नीति परिवर्तन स्कूलों को उन छात्रों की पहचान

करने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए अधिक अनुकूलित दृष्टिकोण पर जोर देता है। कंद्रीय विद्यालयों में, संघर्षरत छात्रों को अब सीखने के अंतराल को दूर करने के लिए अतिरिक्त कोशिंग प्रदान की जाती है, जिससे बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन निश्चित होता है। पुनः परीक्षा प्रणाली रटने के बजाय योग्यता-आधारित परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्रों के सीखने के परिणाम अधिक सार्थक और प्रभावशाली हों। सैनिक स्कूलों में, हाल ही में लागू की गई योग्यता-आधारित परीक्षाएँ व्यावहारिक ज्ञान का आकलन करती हैं, जिससे छात्र तथ्यों को याद करने के बजाय मूल अवधारणाओं को समझने में सक्षम होते हैं। नीति यह सुनिश्चित करके समग्र विकास को बढ़ावा देती है कि असफल छात्रों को शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत ध्यान मिले। दिल्ली सरकार के स्कूलों में, संघर्षरत छात्रों को समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक सुधार के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक समर्थन भी मिलता है। शिक्षक अब सीखने के अंतराल की व्यवहार करने और उसे दूर करने के लिए जिम्मेदार हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे प्रत्येक छात्र की प्रगति में अधिक निवेदन करें। कक्षा शिक्षक अब प्रगति रिकॉर्ड बनाए रखते हैं और विषयों में संघर्ष करने वाले छात्रों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं, जिससे लक्षित हस्तक्षेप रणनीतियाँ बनती हैं। पास होने के लिए कई मौके देकर, नीति विफलता के कलंक को कम करती है, छात्रों को लगे रहने और सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। जो छात्र पहले असफल हुए थे, वे कलंक के जौखियमें थे, लेकिन अब उन्हें दूसरा मौका दिया गया है, जिससे ड्रॉपआउट दर कम हुई है और दृढ़ता की सुविधा मिली है। नौ-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने से बेहतर सीखने के परिणामों के साथ सार्वभौमिक पहुँच का संतुलन बना रहता है। जबाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देकर, यह शिक्षण और मूल्यांकन में सुधार ला सकता है। हालाँकि, इस बदलाव को सफल बनाने के लिए शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण, सुधारात्मक सहायता और छात्रों के आधारभूत कौशल को मजबूत करने के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है। दैश में शिक्षा की निम्न गुणवत्ता के मूल कारणों को संबोधित करने के बजाय, पूरा ध्यान पास/फेल प्रणाली को फिर से लागू करने पर है। समय की मांग है कि सभी पक्षों को अधिक गंभीरता से काम करना चाहिए, और अब समय आ गया है कि शेष मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रयास किए जाएं। परिणामस्वरूप, नीति में नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त समायोजन के साथ संशोधन किया जाना चाहिए, या इसे एक नए, अधिक संतुलित दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। मुख्य लक्ष्य बच्चों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना और उन्हें जीवन कौशल प्रदान करना होना चाहिए।



बिहार सरकार को भारी पड़ता युवाओं पर लाटीचार्ज का मुद्दा

70 वां संयुक्त (प्रारम्भिक) परीक्षा को लेकर 18 दिसंबर से प्रदर्शन जारी है। यत्वावधि को परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन का ऐलान कर रखा था। पुलिस ने पहले ही मैदान के सारे गेट बन्द कर दिये। परीक्षार्थी फिर भी मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ने लगे। उन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया। जब वे इसके बावजूद नहीं रुके तो उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया। उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा के लिये सितम्बर में विज्ञापन जारी हुआ था।

इसमें शामिल होने के लिये लगभग 5 लाख लागा ने आवंटन किया था।



कुमार कृष्णन
लेखक

ब हार में राजनीति कैसे खल दिखाती है यह तब स्पष्ट दिखाइ दिया जब दिसम्बर माह की हाड़ कंपकपाती ठंड के बावजूद आंदोलनरत छात्रों पर पानी की बौछार करवाने की जरूरत उन नीतीश कुमार को पड़ गयी जो स्वयं 1974 के छात्र आंदोलन की उपज हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानि बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद अब दूसरे दलों के नेता भी इस मामले में राजनीति करने लगे हैं। पूरे विषयक ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वही पटना की बर्बातापूर्ण घटना के खिलाफ दूसरे जिलों में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीपीएससी ने जितनी छवि नीतीश कुमार की खराब की है, उतनी किसी तेरीनी नहीं है। ऐसे देश में गवर्नरों के ज्यादा वैकंसी बिहार में आई, लेकिन बीपीएससी ने परीक्षा सही तरीके से नहीं कराई और सबसे ज्यादा बदनामी करा दी। बिहार में बीपीएससी परीक्षा में धंधली को लेकर छात्रों का आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। छात्रों की मांग है कि सभी 912 केन्द्रों में बीपीएससी प्रारम्भिक परीक्षाएं दोबारा हों। इस मांग पर पखवाड़े भर से जारी आंदोलन को कुचलने के लिये बिहार सरकार अब बर्बादी पर उतर आई है। रविवार की रात को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के पास एकत्रित हजारों परीक्षार्थियों पर पुलिस ने भीषण लाठी चार्ज किया और कड़कड़ाई ठंड में पानी की बौछारें की। यहां आंदोलनकारियों का जमावड़ा सुबह से होने लगा था जिन्हें पुलिस बार-बार चेतावनी दे रही थी कि उन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। इसे अनुसुना करते हुए बड़ी संख्या में एकत्र हुए परीक्षार्थी पुलिस के बल प्रयोग से चपेट ली गई हैं। उस अनेक लोगों के

खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज हुई है। नौजवानों के इस जुटान का फायदा लेने के लिये जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी पहुंचे और मुख्य सचिव से मिल आये। लौटकर उन्होंने इस बात का श्रेय लेने की कोशिश की कि हावे 5 प्रतिनिधियों के मिलने की अनुमति लाने में सफल हुए हैं। यदि इसके बाद भी परीक्षार्थी संतुष्ट न हुए तो उससे ऊपर बात की जायेगी ताकि विवाह को जब लाठी चार्ज हो रहा था, तो वे भी मौके से गयब ही हो गये थे। बहरहाल, यह मुद्दा अब लगातार गर्मा रहा है और लोगों में रोष है। बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं जिसके लिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य भर में प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। युवाओं के साथ यह जुल्म और उनकी अनसुनी नीतीश व उनकी गठबन्धन सकार को महांगी पड़ सकती है बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70 लाख प्रमिति परीथि को उत्तराखण्ड

और दुबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अध्यर्थियों पर बाटर कैनन का इस्तेमाल और लाठी चार्ज के मामले को लेकर सोमवार को पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की। राजभवन से निकलने के बाद सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राज्यपाल ने उनकी बातों को सुना। उन्होंने बताया, हूं राज्यपाल ने उनके सामने ही बीपीएससी चेयरमैन से बात की और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को बुलाने की बात कही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने का भी भरोसा दिया है। उन्होंने लाठीचार्ज की जांच की बात भी की है हिप्पपू यादव ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर नाम लिए बिना कहा कि ह्याँफॉड किशोरहन् ने बच्चों को गालियां दीं। वे बच्चों वो ताकत नहीं जानते हैं। निर्दलीय सांसद ने राज्यपाल को एक जानन भी मांगा है। द्वारे गई आपको पूर्ण रूप से रद्द करने और पुनर्परीक्षा कराने तथा लाठीचार्ज के दौरान महिला परीक्षितार्थियों के साथ दुर्व्ववहार की निष्पक्ष जांच तथा प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की है। इससे पहले पप्पू यादव ने एक्स पर एक बीडियो पोस्ट करके प्रशांत किशोर पर अध्यर्थियों को धमकाने का आरोप लगाते हुए लिखा, हृप्रशांत किशोर खुट नया नेता बने हैं, और छात्रों को धमका रहे हैं, अपनी औकात का धौंस दिखा रहे हैं। आज जब धेले भर की चुनावी औकात नहीं है तो अहंकार टपक रहा है, छात्रों के सामने बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। छात्र पुलिस से पिट रहे थे आप पीठ दिखाकर भाग गए, सवाल पूछने पर गाली? हूं पप्पू यादव के मिलने के बाद बीपीएससी के चेयरमैन ने भी राज्यपाल से मिलकर उन्हें पूरी स्थिति से अवगत करा दिया है। पप्पू यादव के सामने ही राज्यपाल ने एक्स पर लाठीचार्जी की चेयरमैन को बुलाया था। दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत अध्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मिला। हालांकि, इस बातचीत का फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला है। इस बीच छात्रों ने धरना जारी रखने का निर्णय लिया है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल अनु कुमारी ने कहा, हुन्होंने हमारी सारी बातों को सुना, ऐसा लगता है कि निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में एक पैमाना होता है, निर्णय लेने का। जांच करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के पटना आने के बाद मुलाकात करवाने का भी आश्वासन दिया। हाराम कश्यप ने कहा, हुन्हांना कहना था कि एक केंद्र पर 18 फ़जार बच्चे हैं। ऐसा पहले भी हुआ है कि एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की गई है।

मनोज श्रीवास्तव पर मोहन की कृपा

सेवा काजय ता मवा जरूर मिलने है , ये हमारे बुजु़गों का अनुभवजावाक्य है । भारतीय प्रशासनिक सेवा एक पूर्व अधिकारी मनोज श्रीवास्तव पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की कृपा बरसते देख तमाम लोगों के पेट में दर्द हो रहा है । राज्यशासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव को 1 जनवरी, 2025 छः वर्ष या 66 वर्ष की आयु पूर्ण होने जो पहले हो, तक की अवधि के लिए आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग ने पद पर नियुक्त किया गया है । मनोज श्रीवास्तव को मैं तब से जानता हूँ जैसे वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुए । मनोज जी 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएस अधिकारी हैं । वे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर प्रमुख सचिव के पास से अप्रैल 2021 में सेवानिवृत्त हु

थे। छोटे कद के मनोज श्रीवास्तव ने वास्तव में बड़े-बड़े कामों को अंजाम दिया। सामान्य परिवार से भाप्रसे में आना उनकी अद्वितीय मेधा का ही परिणाम है। वे मध्यप्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों के प्रिय रहे, क्योंकि उन्हें अपने हर आका की मंशा भांपना भली-भाँती आता है। उनकी सरकारी सेवाओं की एक लंबी और गौरवपूर्ण सूची है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न घोषणाओं में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वे जब इंदौर इंदौर कलेक्टर, थे तब उनके ऊपर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिव्यगंजय सिंह की महती कृपा थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने इंदौर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलकर दिव्यगंजय विरोधी तमाम बिल्डरों की अनेक बहुमंजिला इमारतों को बारूद से उड़ा दिया था। वे अपनी प्रतिभा के बूते ही प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त, मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव, और वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव जैसे पदों पर कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा, वे पशुपालन समिति और कई अन्य प्रशासनिक इकाइयों में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मनोज श्रीवास्तव को प्रदेश सरकार के अलावा सधं और भाजपा का समर्थन कोई एक दिन में हासिल नहीं हुआ। इसके पीछे उनकी लाल्मी साधना है। वे हर मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिलाने में सिद्धहस्त अधिकारी रहे हैं। वे अद्यता है। खूब पढ़ते हैं, खूब लिखते हैं। उनकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक जमाने में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को खुश करने के लिए धर्म और राष्ट्रगीत वन्देमातरम तक पर लघु पुस्तकाएं लिखीं। वे जिस पद पर रहे, उस पद पर अपने अपको

प्रमाणित करके ही निकले। उन्हें प्रशासनिक सेवा में हर समय मेवा ही नहीं मिला, बनवास भी मिला। वे राजस्व मंडल में भी सजा खुगते वाले प्रशासनिक अधिकारीयों में शामिल हैं, किन्तु उन्होंने राजस्व मंडल में भी कमल का धमाल किया था वे सेवानिवृत्त के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब सक्रिय हैं। मनोज श्रीवास्तव मुझसे उप्र में छोड़े हैं किन्तु ज्ञान में बहुत बड़े हैं। मेरे जैसे अज्ञानियों का अनुभव है कि मध्यप्रदेश में भाजपा और संघ की रितिनीति पर प्रदेश में सबसे जायदा और मुखरता से जितना काम पत्रकारों में विजय मोहन तिवारी ने किया उतना ही काम प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में मनोज श्रीवास्तव ने किया। दोनों भाजपा की सनातन ध्योगी के उद्घोषक हैं। जो काम वे सरकारी सेवा में नहीं कर पाए उसे तिवारी जा प्रश्न के सूचना आयुक्त बन गए और मनोज श्रीवास्तव पहले प्रशासनिक इकाई पुर्णगठन आयोग के सदस्य बनाये गए और बाद में प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त। प्रशासनिक हल्कों में खबर गर्म है की मनोज श्रीवास्तव के पद पर नियुक्ति से पहले, इस पद के लिए पूर्व पुख्त सचिव वीरा राणा और रिटायर्ड एसीएस मलय श्रीवास्तव के नामों पर भी चर्चा हो रही थी। दरअसल, 30 सितंबर को वीरा राणा के रिटायरमेंट के दिन उन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने का आदेश जारी होने वाला था, लेकिन अनुराग जैन को मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद समीकरण बदल गए, और मनोज श्रीवास्तव के नाम की लाटरी खुल गयी। मनोज श्रीवास्तव का भाजपा और संघ प्रेम सबके ऊपर भारी पड़ा। भाजपा और संघ की नीतियों के मुखर समर्थक मनोज हानि दिया था। उन्हें उनका सेवा आ के लिए केंद्रीय हिंदू संस्थान द्वारा दिए जाने वाले स्वामी विवेकानंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मनोज श्रीवास्तव को कांसिल फॉर इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशंस एंड नेहरू सेंटरल, साउथ बैंक्स, लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमानन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में वह महात्मा मांधी द्वारा स्थापित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के हिंदी वर्णन से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका अक्षरा के प्रधान संपादक हैं। मनोज जी ने एक -दो नहीं बल्कि पूरी 38 पुस्तकें लिखी। उन्हें उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कबीर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। वह सहित्य के क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं, कभी-कभी उनकी सक्रियता से ईर्ष्या भी होने लगती है।

